

शहरी वित्त और 16वें वित्त आयोग का मुद्दा

प्रलिस के लयि:

[74वाँ संवधान संशोधन](#), [राज्य नीतिके नरिदेशक सदिधांत](#), [रज़िरव बैंक ऑफ इंडया](#), [भोगोलकि सूचना परणाली](#), [वतित आयोग](#)

मेन्स के लयि:

[शहरी स्थानीय नकियाँ के समकष वतित्तीय कमी](#), [शहरी स्थानीय शासन के सशकतीकरण के उपाय](#) ।

[स्रोत: द हद्वि](#)

चरचा में क्यौं?

भारत में [16वें वतित्त आयोग \(Finance Commission- FC\)](#) से संबंघति हाल के घटनाक्रमों ने राजकोषीय वकिेद्रीकरण से संबंघति महत्त्वपूर्ण मुद्दों को उजागर कया है, [वशेष रूप से शहरी कषेत्रों और संघीय ढाँचे](#) के भीतर उनकी [वतित्तीय स्थरिता](#) पर ध्यान केंद्रति कया है ।

- वशिव बैंक ने अनुमान लगाया है क अगले दशक में बुनयादी शहरी बुनयादी ढाँचे के लयि **840 बलियन अमरीकी डॉलर** की आवशयकता होगी ।

शहरी कषेत्रों में वतित्तीय स्थरिता संबंघी मुद्दे कया हैं?

- शहरीकरण की चुनौतियाँ:** भारत के शहरी कषेत्र, जो भारत के **सकल घरेलू उत्पाद में 66% और कुल सरकारी राजस्व में लगभग 90% का योगदान करते हैं**, भारी बुनयादी ढाँचे तथा वतित्तीय चुनौतियों का सामना करते हैं ।
 - महत्त्वपूर्ण आर्थिक केंद्र होने के बावजूद, **शहरों को अपर्याप्त वतित्तीय सहायता प्राप्त होती है तथा अंतर-सरकारी हस्तांतरण सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.5% होता है**, जसिसे आवशयक सेवाएँ प्रदान करने और बुनयादी ढाँचे को बनाए रखने की उनकी कषमता प्रभावति होती है ।
- वतित्तीय हस्तांतरण मुद्दे:** [शहरी स्थानीय नकियाँ](#) को धनराशिका हस्तांतरण अन्य वकिसशील देशों की तुलना में काफी कम है ।
 - उदाहरण के लयि, [दकषण अफ्रीका](#) अपने [सकल घरेलू उत्पाद](#) का 2.6%, मेक्सिको 1.6%, फलीपीस 2.5% और ब्राज़ील 5.1% अपने शहरों को आवंटति करता है ।
 - यह कमी **शहरी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता** को प्रभावति करती है, जो क **GST** की शुरुआत से और भी बदतर हो गई है, जसिने **ULB** के अपने कर राजस्व को कम कर दया है ।
- संसाधनों का दोहन:** 221 नगर नगिर्मों (2020-21) के [रज़िरव बैंक ऑफ इंडया सरवेकषण](#) से पता चला है क इनमें से **70% से अधिक नगिर्मों** के राजस्व में गरिवट देखी गई, जबक इसके वपिरीत, उनके व्यय में लगभग 71.2% की वृद्धि हुई ।
 - RBI की रपिरीट में संपत्तिकर के सीमति कवरेज और नगर नगिम के राजस्व को बढ़ाने में इसकी वफलता पर भी प्रकाश डाला गया है ।
 - [आर्थिक सहयोग एवं वकिस संगठन \(OECD\)](#) के अनुसार भारत में **संपत्तिकर संग्रह दर (GDP अनुपात में संपत्तिकर) दुनया में सबसे कम है** ।
- अनुदान में कमी:** वशेषज्जों का तरक है क **GST** ने न केवल चुंगी समाप्त कर दी, बल्क कई छोटे उद्यमियों के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा, जसिके परिणामस्वरूप **शहरी स्थानीय नकियाँ के कर राजस्व में उल्लेखनीय कमी** देखी गई ।
 - पहले शहरी केंद्रों के **कुल राजस्व व्यय का लगभग 55% चुंगी** से पूरा कया जाता था, जो अब काफी कम हो गया है ।
- अन्य मामले:**
 - जनगणना डेटा संबंघी चतिाएँ:** अद्यतन [जनगणना आँकड़ों \(2011 से\)](#) की अनुपस्थति शहरी आबादी और उसकी आवशयकताओं का सटीक आकलन करने में चुनौती पेश करती है ।
 - यह पुराना डेटा साकष्य-आधारति राजकोषीय हस्तांतरण योजना को प्रभावति करता है, जो क **गतशील शहरीकरण प्रवृत्तियों**, जसिमें **टयिर-2 और 3 शहरों की ओर प्रवास भी शामिल है**, को उजागर करने के लयि महत्त्वपूर्ण है ।
 - नीतगित वकित्तियाँ:** समानांतर एजेंसियों और योजनाएँ, जैसे क [सांसद/वधायक स्थानीय कषेत्र वकिस नधि](#), स्थानीय सरकारों की वतित्तीय स्वायत्तता को कमज़ोर करती हैं, इच्छति संघीय ढाँचे को वकित्त करती हैं और शहरी शासन तथा सेवा वतिरण को जटलि बनाती हैं ।
 - कम करयात्मक स्वायत्तता:** [महामारी](#) के दौरान, राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर के नेताओं को [आपदा न्यूनीकरण रणनीतियों](#) पर

वर्षाव करके देखा गया, हालाँकि नगर नगिमों के प्रमुखों को इस समूह में शामिल नहीं किया गया।

- स्थानीय सरकारों को राज्य सरकारों के सहायक के रूप में मानने का पुराना दृष्टिकोण नीतिगत प्रतमान पर हावी बना हुआ है।
- संरचनात्मक मुद्दे: कुछ शहरी स्थानीय सरकारों के पास बुनियादी ढाँचे और मानव संसाधन नहीं हैं। जबकि कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों के लिये नियमिता चुनाव नहीं कराए जाते हैं। इससे उनके कामकाज और सेवाओं की डलिवरी प्रभावित होती है।

16वें वतित्त आयोग के लिये प्रमुख वचिरणीय वषिय क्या हैं?

■ परचिय:

- भारत में वतित्त आयोग भारतीय संवधिन के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापतत एक संवैधानकत नकिया है।
 - इसका प्राथमकत कारय केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वतित्त संसाधनों के वततरण की सफिरश करन है।
- 15वें वतित्त आयोग का गठन 27 नवंबर, 2017 को कया गया था। इसने अपनी अंतरमि और अंतमि रपिरट के माध्यम से 1 अप्रैल, 2020 से शुरु होने वाली छह वर्षों की अवध को कवर करते हुए सफिरशें कीं।
 - पंद्रहवें वतित्त आयोग की सफिरशें वतित्त वर्ष 2025-26 तक मान्य हैं।

■ संदर्भ की शरतें:

- कर आय का वभाजन: संवधिन के अध्याय-1 के तहत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करों के वततरण की सफिरश करन।
 - इसमें कर आय से राज्यों के बीच शेरों का आवंटन शामिल है।
- सहायता अनुदान के सदिधांत: भारत की संचति नधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नरितरति करने वाले सदिधांतों की स्थापना करन।
 - इसमें वशेष रूप से संवधिन के अनुच्छेद 275 के अंतरगत राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाने वाली राशिका नरिधारण करन शामिल है।
- स्थानीय नकियाओं के लिये राज्य नधि को बढाना: राज्य की समेकत नधि को बढाने के उपायों की पहचान करन।
 - इसका उद्देश्य राज्य के अपने वतित्त आयोग द्वारा की गई सफिरशों के आधार पर, राज्य के भीतरपंचायतों और नगर पालकियाओं के लिये उपलब्ध संसाधनों को पूरक बनाना है।
- आपदा प्रबंधन वतित्तपोषण का मूल्यांकन: आयोग आपदा प्रबंधन पहल से संबंधित वर्तमान वतित्तपोषण संरचनाओं की समीक्षा कर सकता है।
 - इसमें आपदा प्रबंधन अधनियम, 2005 के तहत बनाए गए फंड की जाँच करन और सुधार या बदलाव के लिये उपयुक्त सफिरशें प्रस्तुत करन शामिल है।

असम सरकार ने राज्य वतित्त आयोग में नयुक्तकी

- असम सरकार ने सातवें असम राज्य वतित्त आयोग का गठन कया है, जसके अध्यक्ष लेफ्टनैट जनरल राणा प्रताप कलति (सेवानवृत्त) और छह अन्य सदस्य होंगे।
- 73वें और 74वें संवधिन संशोधन द्वारा गठित राज्य वतित्त आयोग (State Finance Commission- SFC) का उद्देश्य भारत में राज्य तथा उप-राज्य स्तर पर राजकोषीय संबंधों को सुव्यवस्थित करन है, जसकी नयुक्तियाँ भारतीय संवधिन के अनुच्छेद 243-I एवं 243-Y द्वारा शासित होती हैं।
 - अनुच्छेद 243-I: राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक पाँच वर्ष में एक वतित्त आयोग गठित करने का आदेश देता है।
 - अनुच्छेद 243Y: इसके तहत गठित वतित्त आयोग नगरपालकियाओं की वतित्त स्थिति की समीक्षा भी करेगा और राज्यपाल को सफिरशें करेगा।

शहरी वतित्त को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- नगर नगिम के राजस्व को मज़बूत करन: सभी वतित्त आयोगों ने नगर नगिम के वतित्त को बेहतर बनाने हेतु संपत्तकित राजस्व को बढाने की आवश्यकता को पहचाना है। उदाहरण के लिये:
 - 12वें वतित्त आयोग ने संपत्तकित प्रशासन में सुधार के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographical Information System- GIS) और डजिटलीकरण के उपयोग को प्रोत्साहित कया।
 - 14वें वतित्त आयोग ने अनुशांसा की कनगर नकियाओं को खाली भूमि पर कर लगाने में सक्षम कया जा।
- कर प्रशासन का आधुनकिकरण: पुरानी प्रणालियाँ अकुशलता और लीकेज का कारण बनती हैं। स्थानीय नकियाय संपत्तकित मूल्यांकन, ई-फाइलिंग और ऑनलाइन भुगतान के लिये डजिटल प्लेटफॉर्म लागू कर सकते हैं।
 - इससे पारदर्शता बढती है, नागरकों को सुवधि मिलती है तथा संग्रह दर में वृद्धि होती है।
- वशिषिट सेवाओं के लिये उपयोगकर्त्ता शुल्क का पता लगाएँ: एक व्यापक कर संरचना के बजाय, कुछ सेवाओं हेतु उपयोगकर्त्ता शुल्क हो सकते हैं। यह पार्कगि, थोक जनरेटर के लिये अपशिषिट संग्रह या मनोरंजन सुवधियाँ पर लागू हो सकता है।
 - मुख्य बात यह सुनिश्चित करन है कि शुल्क उचित हो और सेवा प्रदान करने की लागत को प्रतबिबिति करे। बंगलुरु जैसे शहरों ने अपशिषिट प्रबंधन के लिये उपयोगकर्त्ता शुल्क को सफलतापूर्वक लागू कया है।
- रणनीतिक संपत्तकित प्रबंधन: स्थानीय नकियाओं के पास अक्सर कम उपयोग वाली संपत्तकियाँ होती हैं। इन्हें वाणज्यिक स्थानों, बाज़ारों या पार्कगि स्थलों के विकास के लिये सार्वजनिक-नजी भागीदारी (Public-Private Partnerships- PPP) के माध्यम से मुद्रीकृत कया जा सकता

है।

- इससे स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में करिये की आय और आर्थिक गतिविधित्पन्न होती है। **वशिव बैंक** स्थानीय सरकारों के लिये बुनयिादी ढाँचे के विकास के लिये वतितपोषण और वशिषज्जता तक पहुँचने के साधन के रूप में PPP की सफिरशि करता है।
- **स्थानीय व्यवसायों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:** एक संपन्न स्थानीय अर्थव्यवस्था से **स्थानीय निकायों के लिये उच्च कर राजस्व** की प्राप्ता होती है। इसके लिये किये जाने वाले पहलों में व्यवसाय लाइसेंस को सुव्यवस्थित करना, स्टार्टअप के लिये कर छूट की पेशकश करना या नवाचार केंद्र स्थापति शामिल हो सकता है।
 - अमेरिका में टेक्सास में स्थिति शहर ऑस्टनि उद्यमियों के लिये अनुकूल परविश के लिये जाना जाता है, जिसके कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई।
- **सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) का अन्वेषण:** ये बाज़ार लाभ सृजन के साथ-साथ सामाजिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित वाले सामाजिक उद्यमों को पूंजी जुटाने का माध्यम प्रदान करते हैं। स्थानीय निकाय एक नया SSE स्थापति करने या पहले से मौजूद किसी के साथ सहयोग करने की व्यवहार्यता की जाँच कर सकते हैं।
 - इससे उन **पहलों के लिये नविश** आकर्षित हो सकता है जनिसे स्थानीय सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्तिके साथ स्थानीय निकाय के लिये राजस्व उत्पन्न होता है।
- **वैल्यू कैपचर तंत्र का करयान्वन:** इसमें **सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं** के परिणामस्वरूप नज्ी संपत्तियों के मूल्य में हुए वर्द्धन के एक हसिसे का अधगिरहण (कैपचर) करना शामिल है।
 - **हॉन्गकॉन्ग** एक ऐसे शहर का प्रमुख उदाहरण है जो अवसंरचना परियोजनाओं के लिये **भूमिभूल्य कैपचर** का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है।

नषिकरष:

राजकोषीय हस्तांतरण सदिधांतों की पुनः समीक्षा करके, वर्तमान शहरीकरण गतिशीलता के आधार पर कार्यप्रणाली को अद्यतन करके तथा शहरी क्षेत्रों के लिये IGT में पर्याप्त वृद्धिकी सफिरशि कर उक्त **चुनौतियों का समाधान करने में 16वाँ वतित आयोग की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण** है।

- इन सफिरशियों के परिणाम **दूरगामी** होंगे, जो **भारत के आर्थिक विकास**, सामाजिक समानता लक्ष्यों और शहरी केंद्रों में पर्यावरणीय स्थिरता प्रयासों को प्रभावित करेंगे।
- प्रभावी कार्यान्वयन के लिये नीतियों को संरेखित करने और देश में सतत् शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिये **केंद्र तथा राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों** की आवश्यकता है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न: कया 16वें वतित आयोग द्वारा नधियों का वर्द्धति न्यागमन भारत में शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के समक्ष वदियामान वतित संबंधी प्रणालीगत चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकता है। वशिलेषण कीजिये।

और पढ़ें: [16वाँ वतित आयोग](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति पर वचिर कीजिये: (2023)

1. जनांकिकीय नषिपादन
2. वन और पारस्थितिकी
3. शासन सुधार
4. स्थरि सरकार
5. कर एवं राजकोषीय प्रयास

समसृतर कर-अवकरण के लिये पंदरहवें वतित आयोग ने उपर्युक्त में से कतिने को जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा नकिष के रूप में पर्युक्त कया?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) केवल चार
- (d) सभी पाँच

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत के संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको संसद के समक्ष रखा जाए? (2012)

1. केंद्रीय वित्त आयोग की सफारिशें
2. लोक लेखा समिति की रिपोर्ट
3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट
4. राष्ट्रीय अनुसूचि जाति आयोग की रिपोर्ट

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (2011)

- (a) यह बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये विदेशी पूंजी की आमद को प्रोत्साहित करता है।
- (b) यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बीच वित्त के उचित वितरण की सुविधा प्रदान करता है।
- (c) यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- (d) इस संदर्भ में कोई भी कथन (a), (b) और (c) सही नहीं है।

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की विचिन्ना कीजिये जो स्थानीय शासन की वित्त-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये पिछले आयोगों से भिन्न हैं। (2013)